अण्डमान निकोबार द्वीप समाचार

रजि.न.34300/80 | संख्या 205 | श्री विजय पुरम, मंगलवार, 29 जुलाई 2025 | web: www. andaman.gov.in | 2.00 रूपए

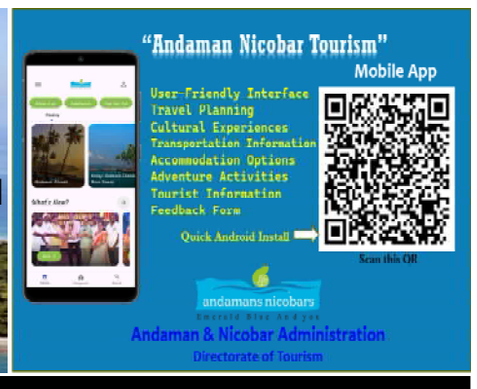

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के लक्ष्यों का आधारभूत स्तर पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए द्वीपों में निपुण भारत के अनुरूप एफएलएन मिशन की शुरूआत

श्री विजय पुरम, 28 जुलाई।

केंद्र शासित प्रदेश अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह ने निपुण भारत के अनुरूप आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता (एफएलएन) मिशन शुरू किए हैं, जिससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के लक्ष्यों का आधारभूत स्तर पर कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके। निपुण भारत मिशन (समझ के साथ पढ़ने और संख्यात्मकता में दक्षता के लिए राष्ट्रीय पहल) को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा 5 जुलाई, 2021 को समग्र शिक्षा के अंतर्गत शुरू किया गया था। इस मिशन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत का प्रत्येक बच्चा 2026–27 तक कक्षा–3 के अंत तक आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता (एफएलएन) प्राप्त कर ले। निपुण भारत मिशन के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, केंद्र शासित प्रदेश अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई लक्षित पहल शुरू की हैं कि प्रत्येक बच्चा कक्षा–3 के अंत तक आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त कर ले। निपुण भारत और एनईपी–2020 के अंतर्गत कुछ प्रमुख पहल नीचे दी गई हैं।

- **जादुई पिटारा:** एनसीईआरटी द्वारा एनईपी 2020 के फाउंडेशनल स्टेज पाठ्यक्रम (आयु 3–8) के अंतर्गत शुरू की गई एक खेल–आधारित शिक्षण सामग्री (एलटीएम) किट, सभी स्कूलों में वितरित की गई। वर्कशीट, गतिविधि पुस्तकें और कहानी–आधारित सामग्री जैसे नवीन बाल–केंद्रित संसाधनों ने कक्षा में जुड़ाव को बढ़ाया है।
- **विद्या प्रवेश:** एनसीईआरटी द्वारा विकसित 3 महीने का खेल–आधारित स्कूल तत्परता कार्यक्रम, जो अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह के सभी स्कूलों में लागू प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा और आधारभूत शिक्षा के लिए एनईपी–2020 के दृष्टिकोण के अनुरूप है।
- **एचओआई और शिक्षकों का क्षमता निर्माण:** एनईपी–2020 और निपुण भारत मिशन के लक्ष्यों के अनुरूप, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह के शिक्षा निदेशालय ने संस्थानों के प्रमुखों और शिक्षकों के निरंतर व्यावसायिक विकास को प्राथमिकता दी है और इसके लिए प्रशिक्षण प्रदान करता है। इन प्रयासों का उद्देश्य शैक्षणिक प्रथाओं, नेतृत्व क्षमताओं और कक्षा की प्रभावशीलता को बढ़ाना है–अंततः यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चा वांछित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बुनियादी साक्षरता, संख्यात्मकता और दक्षता प्राप्त करे।
- **अंकुरण:** अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह के शिक्षा विभाग के अंतर्गत

राज्य शिक्षा संस्थान द्वारा एफएलएन को माध्यमिक स्तर तक मज़बूत करने के लिए एक मिशन। #NEP2020 और #NCFSE2023 के साथ संरेखित, यह सीखने के अंतराल को पाटता है, संघर्षरत शिक्षार्थियों का समर्थन करता है और आलोचनात्मक सोच को पोषित करता है और आजीवन सफलता के लिए मज़बूत नींव तैयार करता है।

- **ईसीसीई (प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा):** एनईपी–2020 के दृष्टिकोण के अनुरूप, केंद्र शासित प्रदेश अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह ने आजीवन शिक्षा और विकास के लिए एक मजबूत आधार सुनिश्चित करने हेतु ईसीसीई को लागू किया है। स्कूलों में ईसीसीई बालवाटिका कक्षाओं के माध्यम से, निगरानी और मार्गदर्शन सहायता, अभिभावक सहभागिता गतिविधियाँ, खिलौना आधारित और खेल आधारित शिक्षण गतिविधियाँ आदि पूरे केंद्र शासित प्रदेश में लागू की गई हैं।
- **नामांकन अभियान:** शिक्षा निदेशालय ने दक्षिण अण्डमान तथा विम्बर्लीगंज क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में छात्रों का नामांकन बढ़ाने के लिए एक व्यापक पहल की शुरुआत की। नामांकन बढ़ाने के लिए गाँवों का दौरा, डेमो कक्षाएं और नामांकन मेले जैसी आउटरीच गतिविधियाँ आयोजित की गईं। परिणामस्वरूप, दक्षिण अण्डमान तथा विम्बर्लीगंज क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में सत्र 2025–26 के दौरान 1782 नए प्रवेश हुए हैं।
- **बैगलेस डे:** एनईपी–2020 के अनुरूप कक्षा 6वीं से 8वीं के लिए 10 बैगलेस डे की अभिनव अवधारणा, सत्र 2024–25 में अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह के सभी स्कूलों में शुरू की गई। इस पहल का उद्देश्य छात्रों के सीखने के अनुभवों को बढ़ाना और उन्हें पूरक बनाना है। बैगलेस डे छात्रों को पारंपरिक कक्षा सेटिंग से परे विभिन्न गतिविधियों में शामिल होने के अवसर प्रदान करते हैं।
- **डिजिटल एकीकरण:** एनईपी–2020 के दृष्टिकोण और निपुण भारत के उद्देश्यों के अनुसार, शिक्षा निदेशालय, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह ने शिक्षण–अधिगम प्रक्रियाओं को बढ़ाने, मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता (एफएलएन) परिणामों में सुधार करने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुँच सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल उपकरणों और प्लेटफार्मों को सक्रिय रूप से अपनाया है, यहाँ तक कि दूरस्थ द्वीपों में भी राज्य शिक्षा संस्थान (एसआईई) और डॉ. एस. राधाकृष्णन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) द्वारा तैयार ई–सामग्री, वीडियो पाठ आदि के माध्यम से।
- **बाला विशेषता:** एनईपी–2020 के लक्ष्यों और निपुण भारत मिशन के उद्देश्यों के अनुरूप, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह के सरकारी स्कूलों ने दृश्य, अनुभवात्मक और पर्यावरण अनुकूल शिक्षा के माध्यम से मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता को बढ़ाने के लिए एक अभिनव रणनीति के रूप में बाला (शिक्षण सहायता के रूप में निर्माण) को लागू किया है।
- **समावेशी शिक्षा:** एनईपी–2020 के परिवर्तनकारी दृष्टिकोण के तहत, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह समावेशी शिक्षा को प्राथमिकता देता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी बच्चे–क्षमता, पृष्ठभूमि या परिस्थिति की परवाह किए बिना–गुणवत्तापूर्ण आधारभूत शिक्षा तक समान पहुंच प्राप्त करें। इसके अलावा, समावेशी शिक्षा को मजबूत करने में प्रमुख प्रवर्तक के रूप में, शैक्षिक खंडों में संसाधन केंद्र कार्यात्मक हैं। एसआईई द्वारा गर्मियों की छुट्टियों के दौरान ब्रेल कक्षाएं भी संचालित की जाती हैं।
- **नवचेतना:** राष्ट्रीय शैक्षिक नीति–2020 के साथ संरेखित जीवन कौशल और ड्रग शिक्षा पर एक नई चेतना, एक स्वस्थ समाज बनाने के लिए समग्र स्वास्थ्य, पोषण, शारीरिक शिक्षा, फिटनेस और कल्याण के लिए पाठ्यक्रम और शैक्षणिक पहलों के महत्व पर ज़ोर देती है। इस पहल के तहत, 38 सीआरसी से 104 नोडल शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन (एल्डर लाइन–14567)

अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में वृद्धजन देखभाल सेवाओं का सुदृढ़ीकरण

श्री विजय पुरम, 28 जुलाई।

भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान (एनआईएसडी) के माध्यम से, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के समाज कल्याण निदेशालय और सेवा प्रदाता, अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड, नई दिल्ली के सहयोग से, अटल वयो अभ्युदय योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन–एल्डर लाइन 14567 शुरू की है। इस महत्वपूर्ण पहल का उद्देश्य देश भर के वृद्ध नागरिकों की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण सुनिश्चित करना है। केंद्र शासित प्रदेश अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में, यह हेल्पलाइन 24 दिसंबर, 2024 से चालू है और यह प्रतिदिन सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक महिला एवं बाल विकास नियंत्रण कक्ष भवन, वीआईपी रोड, श्री विजय पुरम, जंगलीघाट से कार्य करती है। टोल–फ्री नंबर 14567 के माध्यम से सुलभ यह हेल्पलाइन सूचना, मार्गदर्शन, भावनात्मक समर्थन और क्षेत्र–स्तरीय हस्तक्षेप सहित निःशुल्क सेवाएँ प्रदान करती है। यह बुजुर्गों की चिंताओं, शिकायतों और आवश्यकताओं को दूर करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया प्रणाली के रूप में कार्य करती है। इस मंच के माध्यम से, बुजुर्ग नागरिकों को समर्थन, हस्तक्षेप और सुरक्षा के लिए एक आवाज़ और माध्यम प्रदान किया जाता है।

अपनी स्थापना के बाद से, वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन (एनएचएससी) को 500 से अधिक कॉल प्राप्त हुए हैं। इनमें से 103 कॉल आधिकारिक रूप से पंजीकृत की गईं और 101 मामलों का सफलतापूर्वक समाधान किया गया है। संबोधित मुद्दों की प्रकृति में सूचना के लिए अनुरोध, भावनात्मक समर्थन, शारीरिक और मानसिक शोषण की शिकायतें, आर्थिक उपेक्षा, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, पुरानी बीमारियाँ और अन्य कल्याण संबंधी चिंताएँ शामिल हैं। प्रत्येक मामले को करुणा, तत्परता और उचित क्षेत्र कार्रवाई के साथ संभाला गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वरिष्ठ नागरिकों को वह ध्यान और सेवाएँ प्राप्त हों जिनके वे हक़दार हैं।

एक उल्लेखनीय हस्तक्षेप में, एनएचएससी ने भारतीय स्टेट बैंक में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा सामना किए जाने वाले लंबे प्रतीक्षा समय के बारे में एक शिकायत का जवाब दिया। एनएचएससी कर्मियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए, एसबीआई अधिकारियों से सीधे संपर्क किया और एक औपचारिक अनुरोध प्रस्तुत किया, जिसके परिणामस्वरूप बैंक में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक अलग कतार की व्यवस्था सफलतापूर्वक

शेष पृष्ठ 4 पर

जि.प. अध्यक्ष ने अधिकारियों के साथ चालू एवं आगामी विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया

श्री विजय पुरम, 28 जुलाई

दक्षिण अण्डमान जिला परिषद के अध्यक्ष श्री प्रकाश अधिकारी ने श्री सुशांत पधा, दक्षिण अण्डमान जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती वर्षा, लम्बा लाइन स्थित विवेकानंद केंद्र विद्यालय के सचिव, उपाध्याय श्री भूमिनाथन और जिला परिषद सदस्य श्रीमती प्रमिला कुमारी, श्री अब्दुल बशीर, श्री अब्दुल अज़ीज़, श्री ए. उमर और कार्यकारी अभियंता की अपनी इंजीनियरों की टीम के साथ दक्षिण अण्डमान में चल रही और आगामी विकास परियोजनाओं का व्यापक निरीक्षण किया। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार टीम ने पोर्ट मोट

स्थित विवेकानंद केंद्र जिला परिषद विद्यालय, विम्बर्लीगंज स्थित चिल्ड्रन पार्क, बम्बूफ्लाट स्थित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शोर प्वाइंट स्थित पर्यावरण–अनुकूल कॉटेज, शोर प्वाइंट स्थित विवेकानंद केंद्र जिला परिषद विद्यालय, प्रस्तावित कब्रिस्तान स्थल, मंगलूटान स्थित विवेकानंद केंद्र जिला परिषद विद्यालय, गुप्तापाड़ा स्थित सीता मंदिर के पास शॉपिंग कॉम्प्लेक्स–सह–ग्रामीण हाट के निर्माण का दौरा किया। इस दौरान, चल रहे कार्यों को शीघ्र पूरा करने, निर्धारित समय पर बुनियादी ढाँचे का विकास सुनिश्चित करने और प्रस्तावित स्थल पर प्रारंभिक कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए।

अटल टिंकरिंग लैब के प्रभारियों के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण शुरू

श्री विजय पुरम, 28 जुलाई

सरकारी और निजी स्कूलों के एटीएल (अटल टिंकरिंग लैब) प्रभारियों के लिए पाँच दिवसीय व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम (चरण–1) का आज हैडो स्कूल की एटीएल प्रयोगशाला में उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य एटीएल प्रभारियों को व्यावहारिक कौशल से सशक्त बनाना है ताकि वे छात्रों में नवाचार और रचनात्मकता को प्रेरित कर सकें। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए, मुख्य अतिथि के रूप में कार्यालय प्रमुख/उप शिक्षा निदेशक (प्रशासन) श्री ज्ञान शील दुबे ने ऐसे व्यावहारिक प्रशिक्षण सत्रों के महत्व पर बल दिया और छात्रों में नवाचार को बढ़ावा देने और रचनात्मक, आवश्यकता–आधारित कार्य मॉडल विकसित करने में उनका समर्थन करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया। इससे पहले, उप शिक्षा निदेशक (विज्ञान) श्री राम प्रवेश ने उपस्थित लोगों का स्वागत किया और वैज्ञानिक सोच और नवाचार को बढ़ावा देने में एटीएल गतिविधियों के महत्व पर प्रकाश डाला और द्वीपों में एटीएल पहलों को मजबूत करने के लिए भविष्य की योजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार श्री सुदीप चक्रवर्ती (डीब्राइट), श्री एम. शक्तिवेल (सोवटेक) और सुश्री अनीशा अहमद (आईटीआई), प्रशिक्षण सत्रों के संसाधन व्यक्ति हैं। गोल टेकरी स्कूल, कमोर्टा से लेकर डिगलीपुर स्कूल तक के स्कूलों के एटीएल प्रभारी इंटरैक्टिव समूह गतिविधियों और व्यावहारिक सत्रों के माध्यम से प्रशिक्षण में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम एटीएल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्कूलों में नवाचार और अनुभवात्मक शिक्षा की संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

गणेश पूजा उत्सव के मद्देनज़र जिला कार्यालय में बैठक 31 जुलाई को

श्री विजय पुरम, 28 जुलाई।

गणेश पूजा–2025 उत्सव हेतु कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में, 31 जुलाई, 2025 को शाम 5 बजे, दक्षिण अण्डमान के जिला कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में जिलाधीश सह उपायुक्त (दक्षिण अण्डमान) की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की जाएगी। यह पूजा 27 अगस्त, 2025 से प्रारंभ होकर 31 अगस्त, 2025 को मूर्तियों के विसर्जन के साथ समाप्त होगी।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार श्री विजय पुरम और फरारगंज तहसील की गणेश पूजा समितियों के अध्यक्षों/सचिवों को सूचित किया गया है और अनुरोध किया गया है कि वे उपरोक्त तिथि और समय पर श्री विजय पुरम स्थित जिला कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में आयोजित बैठक में सुविधानुसार उपस्थित हों।

कदमतला में चारा उत्पादन के बारे में किसानों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया

श्री विजय पुरम, 28 जुलाई

पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग ने केन्द्रशासित प्रदेश कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (यूटीएटीएमए) योजना के अंतर्गत 22 और 23 जुलाई, 2025 को मध्य अण्डमान के कदमतला स्थित पशु औषधालय में चारा उत्पादन पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को टिकाऊ चारा उत्पादन हेतु ज्ञान और कौशल से लैस करके पशुधन उत्पादकता को बढ़ाना था। इसका संचालन

कदमतला की वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. नज़राना सेन गुप्ता ने किया। इस प्रशिक्षण में कदमतला के प्रधान और एक वार्ड सदस्य ने भी भाग लिया, जिन्होंने पशु पोषण में सुधार और ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिए चारा उत्पादन के महत्व पर अपने विचार साझा किए। इस कार्यक्रम

शेष पृष्ठ 4 पर

सुभाष ग्राम पंचायत में प्रमुख योजनाओं पर कार्यशाला हुई

श्री विजय पुरम, 28 जुलाई

मेरा युवा भारत (MY Bharat) के मुख्य कार्यक्रम के अंतर्गत, भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन आज उत्तर अण्डमान के डिगलीपुर के सुभाष ग्राम पंचायत के सम्मेलन कक्ष में किया गया। इस पहल का उद्देश्य युवाओं और स्थानीय समुदायों के बीच केंद्र द्वारा प्रायोजित प्रमुख केन्द्रीकृत योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, जिनका नागरिकों के सामाजिक–आर्थिक विकास पर सीधा प्रभाव पड़ता है, खासकर ग्रामीण और अर्ध–शहरी क्षेत्रों में। यह कार्यक्रम युवाओं को बदलाव के जागरूक वाहक के रूप में सशक्त बनाने और इंटरैक्टिव सत्रों और चर्चाओं के माध्यम से सूचना और पहुँच के अंतर को पाटने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

कार्यक्रम में उत्तर व मध्य अण्डमान जिला परिषद के अध्यक्ष श्री श्रीभाष दास मुख्य अतिथि थे और डिगलीपुर के प्रमुख श्री दीपांकर मिस्त्री विशिष्ट अतिथि थे, जिन्होंने इस अवसर की शोभा बढ़ाई और सभा को संबोधित किया। दोनों गणमान्य व्यक्तियों ने शासन और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी के महत्व पर बल दिया और उनसे 2047 तक विकसित भारत के विजन को प्राप्त करने के लिए प्रमुख योजनाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया।

कार्यक्रम में लगभग 50 युवा प्रतिभागियों ने भाग लिया, जहाँ डिगलीपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा अधिकारी (आयुष) डॉ. शिप्रा मिस्त्री और डिगलीपुर में उद्योग विभाग की औद्योगिक संवर्धन अधिकारी श्रीमती आफरीन ने विभिन्न योजनाओं के तहत स्वास्थ्य, कल्याण, उद्यमिता और आत्मनिर्भरता के अवसरों पर सत्र आयोजित किए। विचार–विमर्श में विकसित भारत@2047 लक्ष्य की प्राप्ति में युवाओं की भूमिका पर भी चर्चा हुई।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार इससे पहले, उप निदेशक (ओएसडी) श्री सुख रंजन बिस्वास ने प्रतिभागियों का स्वागत किया और उन्हें कार्यक्रम के उद्देश्यों से अवगत कराया। अपने संबोधन में, उन्होंने कहा कि इस तरह की पहल का मुख्य उद्देश्य जागरूक और सशक्त युवाओं का निर्माण करना है, जो समाज में बदलाव के उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकें। उन्होंने सभी गणमान्य व्यक्तियों और प्रतिभागियों को उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए आभार व्यक्त किया।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने वन महोत्सव 2025 मनाया

श्री विजय पुरम, 28 जुलाई।

वन महोत्सव 2025 समारोह के अंतर्गत, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने 26 जुलाई, 2025 को अपने कार्यालय परिसर में फलदार पौधे रोपने का कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी निदेशक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और इस अवसर पर एक फलदार पौधा रोपा। निदेशक ने वन महोत्सव के महत्व पर एक संक्षिप्त व्याख्यान भी दिया, जिसमें इसकी ऐतिहासिक जड़ों, उद्देश्यों और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में वृक्षों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार विभाग के सभी कर्मचारियों ने कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया, इस हरित पहल में योगदान दिया और एक स्वस्थ एवं हरित पर्यावरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ किया।

अण्डमान लॉ कॉलेज ने अनंतिम मेरिट सूची जारी की

श्री विजय पुरम, 28 जुलाई।

अण्डमान लॉ कॉलेज ने अपनी वेबसाइट https://andamanlawcollege.andaman.gov.in और https://collegeadmission.andaman.gov.in/ पर अपनी अनंतिम मेरिट सूची और श्रेणीवार उम्मीदवारों की मेरिट सूची जारी कर दी है। इसे 26 जुलाई, 2025 को कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित किया गया है।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार जिन उम्मीदवारों को अपनी मेरिट सूची से संबंधित कोई आपत्ति/शिकायत है, वे alcadmissions2023/हउंपसण्बवउ पर ईमेल द्वारा अपनी आपत्ति/शिकायत भेज सकते हैं या 2 अगस्त (शनिवार), 2025 को शाम 5 बजे तक कॉलेज कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से जमा कर सकते हैं। इसके बाद प्राप्त किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। इस वर्ष प्रवेश के लिए 1385 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जबकि वार्षिक प्रवेश 45 है।

लॉन्ग आइलैंड स्कूल के छात्रों के लिए शतरंज प्रशिक्षण कक्षाएं आयोजित

लॉन्ग आइलैंड, 28 जुलाई

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के शिक्षा विभाग ने आज मध्य अण्डमान के लॉन्ग आइलैंड के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के छात्रों के लिए शतरंज प्रशिक्षण कक्षाओं का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में लगभग पचास छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जो द्वीप पर पहली बार आयोजित की गई ऐसी पहल का प्रतीक था। प्रशिक्षण सत्र का औपचारिक उद्घाटन लॉन्ग आइलैंड स्कूल के उप–प्रधानाचार्य श्री मुकुंद बरोई ने किया, जिन्होंने शतरंज की बिसात पर औपचारिक रूप से पहली चाल चलकर कार्यक्रम की शुरुआत की। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार छात्रों, जिनमें से कई पहली बार शतरंज से परिचित हुए थे, ने पूरे सत्र के दौरान बहुत खुशी और उत्साह व्यक्त किया। प्रशिक्षण का समापन एक जीवंत वातावरण में, मनोरम तटरेखा के पास, एक साथ आयोजित शतरंज प्रदर्शनी के साथ हुआ, जिसने युवा शिक्षार्थियों को एक अनूठा और यादगार अनुभव प्रदान किया। यह आकलन करने के लिए कि छात्रों ने प्रशिक्षण से कितना सीखा है, प्रशिक्षकों ने उन्हें मैत्रीपूर्ण मैचों में शामिल किया। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को उनके प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया, जबकि सभी प्रतिभागियों को प्रोत्साहन और प्रशंसा के प्रतीक के रूप में उपहार प्रदान किए गए।

टैगोर कॉलेज में चार वर्षीय यूजी एड. प्रोग्राम के लिए काउंसलिंग 4 अगस्त से

श्री विजय पुरम, 28 जुलाई।

श्री विजय पुरम स्थित टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2025–26 के लिए शिक्षा में चार वर्षीय यूजी एड. प्रोग्राम (बी.एससी. बी.एड. गणित और कंप्यूटर विज्ञान, बी.ए. बी.एड. अंग्रेजी, हिंदी और इतिहास) में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की अंतिम मेरिट सूची 25 जुलाई, 2025 को शाम 4 बजे प्रकाशित कर दी गई है और यह सभी संबंधितों की जानकारी के लिए http://collegeadmission.andaman.gov.in पर टैगोर कॉलेज की "Announcements" के अंतर्गत उपलब्ध है। काउंसलिंग की तिथियां, जो पहले 29 और 30 जुलाई, 2025 के लिए निर्धारित थीं और बाद में 4 और 5 अगस्त, 2025 के लिए पुनर्निर्धारित की गईं, अब विभिन्न संस्थानों की काउंसलिंग तिथियों के ओवरलैप होने के कारण पुनर्निर्धारित की गई हैं।

टैगोर कॉलेज में दोनों पाठ्यक्रमों (बी.एससी. बी.एड. और बी.ए. बी.एड.) के लिए काउंसलिंग की तारीखें 4 अगस्त, 2025 को पुनर्निर्धारित की गई हैं। काउंसलिंग का कार्यक्रम इस प्रकार है:

दिनांक	कार्यक्रम	समय
04.08.2025	गणित और कंप्यूटर विज्ञान में बी.एससी. बी.एड. पाठ्यक्रम के लिए परामर्श	सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक
	अंग्रेजी, हिंदी और इतिहास के मुख्य विषय में बी.ए. बी.एड. पाठ्यक्रम के लिए परामर्श	दोपहर 1:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक
06.08.2025	कक्षाओं का प्रारंभ	सुबह 8:40 बजे तक

प्राप्त विज्ञप्ति में सभी पात्र अभ्यर्थियों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने पाठ्यक्रम के अनुसार संशोधित तिथि और समय पर व्यक्तिगत रूप से काउंसलिंग में उपस्थित हों। चयनित अभ्यर्थियों को प्रवेश के दिन सभी मूल प्रमाणपत्र, उनकी एक फोटोकॉपी और आवश्यक शुल्क के साथ जमा करने होंगे, अन्यथा उन्हें प्रवेश के लिए योग्य नहीं माना जाएगा। जो अभ्यर्थी उपरोक्त तिथि और समय पर काउंसलिंग सत्र में उपस्थित नहीं होंगे, उन्हें पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए योग्य नहीं माना जाएगा और मेरिट सूची में अगले पात्र अभ्यर्थी को प्रवेश के लिए योग्य माना जाएगा। अधिक जानकारी के लिए, अभ्यर्थियों को नियमित रूप से कॉलेज प्रवेश पोर्टल देखते रहने की सलाह दी गई है।

'नॉर्थ बे रोड मैराथन–2.0' का सफलतापूर्वक आयोजन

श्री विजय पुरम, 28 जुलाई

शिक्षा एवं खेल निदेशालय और विम्बर्लीगंज के उप शिक्षा कार्यालय ने कल 'नॉर्थ बे रोड मैराथन–2.0' का सफलतापूर्वक आयोजन किया। यह आयोजन सभी के लिए खुला था, जिसमें पुरुषों और स्कूली छात्रों के लिए 10 किलोमीटर की दौड़ और विम्बर्लीगंज शैक्षिक क्षेत्र की महिलाओं और छात्राओं के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ शामिल थी, जो चूना भट्टा (राम मंदिर)–नॉर्थ बे–चूना भट्टा से शुरू होकर वहीं समाप्त हुई। निदेशक (शिक्षा/खेल) श्री विक्रम सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में और स्वराज द्वीप के सहायक आयुक्त श्री सुशांत पधा ने विशिष्ट अतिथि के रूप में पुरुष वर्ग के विजेताओं को नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस आयोजन में 400 से अधिक प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। निदेशक (शिक्षा/खेल) ने अपने समापन भाषण में युवा पीढ़ी से स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और नशीली दवाओं के दुरुपयोग से दूर रहने के लिए खेलों को अपनाने का आग्रह किया। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार होपटाउन ग्राम पंचायत की प्रधान श्रीमती रशीदा और जिला परिषद सदस्य सुश्री मरियम बीबी ने महिला वर्ग के विजेताओं को नकद पुरस्कार प्रदान किए। केनरा बैंक के मुख्य प्रबंधक श्री देवलिन दत्ता ने विम्बर्लीगंज शैक्षिक अंचल के बालक और बालिका वर्ग के विजेताओं को नकद पुरस्कार प्रदान किए। केनरा बैंक ने विजेताओं के लिए नकद पुरस्कार प्रायोजित किए। पुरूषों के 10 किलोमीटर मैराथन में संदीप, एन. ईश्वरन, विशाल को क्रमशः पहला तीन स्थान मिला, जबकि अनिल एक्का और बाला राजू को सांत्वना पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसी प्रकार महिलाओं के 5 किलोमीटर मैराथन में पी. अलंगानल, मिनाची, सुष्मा रॉय को क्रमशः पहला तीन स्थान हासिल हुआ, जबकि निधि मुंडा और रीना लौहार को सांत्वना पुरस्कार मिला। विम्बर्लीगंज शैक्षिक अंचल के लड़कों के लिए आयोजित 10 किलोमीटर में गणेश कुमार, अनाय टेटे, हरि करण तथा के. हर्षित पॉल को क्रमशः पहला, दूसरा, तीसरा और सांत्वना पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसी अंचल की लड़कियों के लिए आयोजित 5 किलोमीटर में सुष्मिता, अभिनया श्री, हर्षिनी और के. दर्शिनी को क्रमशः पहला, दूसरा, तीसरा और सांत्वना पुरस्कार हासिल हुआ।

एनकॉल के लिए नए काउंसलिंग कार्यक्रम पुनर्निर्धारित

श्री विजय पुरम, 28 जुलाई।

कुछ प्रशासनिक कारणों और अंतर–द्वीपीय अभ्यर्थियों के अनुरोध पर, श्री विजय पुरम के स्थानीय समाचार पत्रों में दिनांक 23 जुलाई, 2025 को प्रकाशित काउंसलिंग कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है और यहां के चक्करगांव स्थित अण्डमान कॉलेज (एनकॉल) में स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए नए काउंसलिंग कार्यक्रम को पुनर्निर्धारित किया गया है। काउंसलिंग की पुनर्निर्धारित तिथियाँ निम्नलिखित हैं।

क्रम संख्या	पाठ्यक्रम	सीटों की संख्या	काउंसलिंग की तिथि	परामर्श का समय
1	बी.कॉम	66	13/08/2025	सुबह 9:30 से दोपहर 12:30 बजे तक
2	बी.कॉम (सीएस)	66		
3	बी.बी.ए.	33	13/08/2025	दोपहर 1:30 से शाम 5:00 बजे तक
4	बी.एससी. (मनोविज्ञान)	33		
5	बी.ए. (अंग्रेजी)	66	14/08/2025	सुबह 9:30 से दोपहर 12:30 बजे तक
6	बी.ए. (अर्थशास्त्र)	66		
7	बी.ए. (समाजशास्त्र)	33	14/08/2025	दोपहर 1:30 से शाम 5:00 बजे तक
8	बी.पी.ए. संगीत (हिंदुस्तानी गायन और वाद्य)	33		

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार विभिन्न यूजी पाठ्यक्रमों की अंतिम मेरिट सूची 10 अगस्त, 2025 को कॉमन कॉलेज एडमिशन पोर्टल (सीसीएपी) (https://collegeadmission.andaman.gov.in) पर अपलोड की जाएगी।

कदमतला में चारा उत्पादन के बारे में

पृष्ठ 1 का शेष

में उच्च उपज वाली चारा फसलों की खेती की व्यावहारिक तकनीकों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें पशुओं के लिए पौष्टिक चारे की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु मिट्टी की तैयारी, बीज चयन, सिंचाई और फसल प्रबंधन पर ज़ोर दिया गया। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार प्रतिभागियों को दूध उत्पादन, पशु स्वास्थ्य और समग्र कृषि उत्पादकता बढ़ाने में गुणवत्तापूर्ण चारे की भूमिका के बारे में शिक्षित किया गया। कदमतला के वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी ने व्यावहारिक प्रदर्शन प्रदान किए और किसानों को चारागाह स्थापित करने और उन्हें अपनी कृषि प्रणालियों में एकीकृत करने की प्रक्रिया के बारे में मार्गदर्शन दिया। प्रशिक्षण में यूटीएटीएमए योजना के लाभों पर भी प्रकाश डाला गया, जो किसानों को आर्थिक परिणामों में सुधार के लिए स्थायी कृषि और पशुधन पद्धतियों को अपनाने में सहायता करती है।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में वृद्धजन देखभाल

पृष्ठ 1 का शेष

शुरू हो पाई। इस छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कदम से बुजुर्गों के लिए बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच में काफ़ी सुधार हुआ है और उनके सम्मान की भावना बहाल हुई है।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार इसके अतिरिक्त, एनएचएससी टीम ने पांच प्रमुख स्थानों पर आयुष्मान भारत कार्ड नामांकन अभियान चलाया, जिनमें उल्लास वृद्धाश्रम, अभ्युदय कॉम्प्लेक्स वृद्धाश्रम, चिन्मय मिशन, हैडो वार्ड संख्या–2 और विम्बर्लीगंज पंचायत हॉल आदि शामिल हैं। इन प्रयासों से अब तक 150 से अधिक वरिष्ठ नागरिक लाभान्वित हुए हैं, जिससे उन्हें आयुष्मान भारत योजना के तहत आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच प्राप्त करने में मदद मिली है। जो लोग बिस्तर पर पड़े थे या यात्रा करने में असमर्थ थे, उनके लिए एनएचएससी ने स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के साथ समन्वय किया, ताकि इन सेवाओं की डोरस्टेप डिलीवरी सुनिश्चित की जा सके, जिससे बुजुर्गों को अपने घरों से बाहर निकले बिना अपने कार्ड प्राप्त हो सकें। इसके अलावा, एनएचएससी ने चिन्मय मिशन के माध्यम से दो कमज़ोर बुजुर्ग परिवारों की पहचान की और उन्हें मासिक राशन सहायता प्रदान की, जिससे कठिन समय में उन्हें बहुत जरूरी राहत मिली। हम आयुष्मान भारत टीम, चिन्मय मिशन और अन्य सहयोगियों सहित सभी हितधारकों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, जिनके सहयोग ने इन पहलों के सफल कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह हेल्पलाइन वृद्धजन समुदाय के लिए देखभाल, करुणा और त्वरित कार्रवाई का एक प्रतीक बनी हुई है। किसी भी सहायता, समर्थन या शिकायत निवारण के लिए, वृद्धजनों या उनके परिवार के सदस्यों को राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन 14567 पर संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है–यह एक टोल–फ्री नंबर है जो हमारे वरिष्ठ नागरिकों को सशक्त बनाने और उनकी सुरक्षा के लिए समर्पित है।

अंतर विद्यालय फुटबॉल नॉकआउट टूर्नामेंट

प्राथमिक (बालिका) वर्ग में प्रोथरापुर स्कूल और माध्यमिक वर्ग में बालिका विद्यालय विजयी

श्री विजय पुरम, 28 जुलाई

दक्षिण अण्डमान स्थित उप शिक्षा कार्यालय के खेल अनुभाग ने 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' कार्यक्रम के अंतर्गत दक्षिण अण्डमान शैक्षिक अंचल की प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं की छात्राओं के लिए जंगलीघाट स्कूल मैदान और भातूबस्ती स्कूल मैदान में अंतर–विद्यालय फुटबॉल नॉकआउट टूर्नामेंट का आयोजन किया। आज, दोनों फाइनल मैच (माध्यमिक बालिका और प्राथमिक बालिका) भातूबस्ती स्कूल मैदान में आयोजित किए गए।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राथमिक (बालिका) मैच में, हम्फ्रीगंज के राजकीय प्रवर माध्यमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका (माध्यमिक) श्रीमती सारिला यूनुस मुख्य अतिथि थीं। सहायक निदेशक श्री मोहम्मद इरशाद अहमद माध्यमिक (बालिका) मैच के मुख्य अतिथि थे। अतिथियों ने विजेता और उप विजेता टीमों को ट्रॉफी प्रदान की। प्राथमिक (बालिका) वर्ग में प्रोथरापुर स्कूल ने हम्फ्रीगंज स्कूल को 01–00 गोल से हराया, और माध्यमिक वर्ग में गर्ल्स स्कूल ने जीडीएमएस (एसएस) को 10–01 गोल से हराया।

ओपन स्टेट जूनियर हॉकी चैम्पियनशिप–सह–चयन ट्रायल

श्री विजय पुरम, 28 जुलाई

हॉकी अण्डमान तथा निकोबार ने जूनियर हॉकी टीमों को सलाह दी है कि वे 3 से 4 अगस्त, 2025 को श्री विजय पुरम में आयोजित होने वाली ओपन स्टेट जूनियर हॉकी चैंपियनशिप–सह–चयन ट्रायल के लिए 1 अगस्त को राज्य ओलंपिक संघ कार्यालय, नेताजी स्टेडियम में अपनी प्रवेश प्रक्रिया को अंतिम रूप दें। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार ये ट्रायल 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 में भाग लेने के लिए आयोजित किए जाएँगे, जिसका आयोजन 12 से 23 अगस्त, 2025 तक जालंधर, पंजाब में किया जाएगा।

सूचना, प्रचार और पर्यटन निदेशालय द्वारा प्रकाशित तथा प्रबन्धक, राजकीय मुद्रणालय द्वारा मुद्रित, वितरण तथा विज्ञापन के लिए फोन–229465, प्रधान सम्पादक (प्रभारी) पी. कैरल डी. सोणी
e-mail:dweepsamachar@gmail.com

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
सचिवालय

अधिसूचना

श्री विजय पुरम, दिनांक 23.07.2025

सं..... फाइल सं. 2–116/2025 – राजस्व – अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन, सचिवालय द्वारा जारी अधिसूचना सं. 88/2019/एफ.सं. 2–116/2019–राजस्व, जो अण्डमान तथा निकोबार राजपत्र में दिनांक 17 मई, 2019 को प्रकाशित हुई थी, का अधिक्रमण करते हुए भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी निम्नलिखित अधिसूचना सं. का.आ. 2681 (अ), दिनांक 16 जून, 2025 को आम जनता के सूचनार्थ एतदद्वारा पुनः प्रकाशित किया जाता है।

ह./–
ए. येसु राज
सहायक सचिव (राजस्व)

गृह मंत्रालय
(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली 16 जून, 2025

का. आ. 2681 (अ). – केंद्रीय सरकार, जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का 37) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड 3 उप खंड (पप) तारीख 28 मार्च, 2019 में प्रकाशित भारत सरकार के गृह मंत्रालय (भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1455 (अ) तारीख 26 मार्च, 2019 के अधिक्रमण में, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, यह घोषणा करती है कि भारत की जनसंख्या की जनगणना वर्ष, 2027 के दौरान की जाएगी।

2. उक्त जनगणना के लिए संदर्भ तारीख, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के और संघ राज्यक्षेत्र जम्मू–कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड राज्यों के हिमाच्छादित असमकालिक क्षेत्रों के सिवाय, मार्च, 2027 के पहले दिन के 00:00 बजे होंगी।

3. संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के लिए और और संघ राज्यक्षेत्र जम्मू–कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड राज्यों के हिमाच्छादित असमकालिक क्षेत्रों के लिए संदर्भ तारीख अक्तूबर, 2026 के पहले दिन के 00:00 बजे होंगी।

फा. सं. 9/8/2025–सीडी (सीइएन),
मृत्युंजय कुमार नारायण
भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से 10.33 करोड़ महिलाओं को मिली राहत, स्वच्छ ऊर्जा ने बढ़ाया सशक्तिकरण

नई दिल्ली, 28 जुलाई।

केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का ऊर्जा क्षेत्र तेजी से बदल रहा है। स्वच्छ ईंधन के इस्तेमाल से महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के तहत अब तक 10.33 करोड़ महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन दिए जा चुके हैं, जिससे उन्हें रसोई के धुएं से मुक्ति और गरिमा से भरा जीवन मिला है।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि अब तक देश में 1.51 करोड़ घरों में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) की सुविधा पहुंच चुकी है। वहीं सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) नेटवर्क अब भारत के 96: भूभाग और 99: जनसंख्या को कवर करता है, जिससे स्वच्छ ऊर्जा की पहुंच बहुत आसान हो गई है। हरदीप पुरी ने कहा कि महिलाएं अब केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि ऊर्जा क्षेत्र में नेतृत्व की भूमिका निभा रही हैं। वे बायोगैस संयंत्र, रिटेल फ्यूल आउटलेट्स और एलपीजी वितरण जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण लेकर काम कर रही हैं। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2024–25 में 42,800 टन कम्प्रेस्ड बायोगैस (CBG) की खरीद की गई है, जिससे भारत में हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिल रहा है।

उन्होंने कहा, "आज की भारतीय महिला केवल उपभोक्ता नहीं, बल्कि देश के ऊर्जा भविष्य को आकार देने वाली

नेतृत्वकर्ता बन चुकी है।" पुरी ने यह भी बताया कि भारत अब ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है। सरकार ने 99 प्रतिशत 'नो–गो' क्षेत्रों को हरी झंडी दे दी है और 10 लाख वर्ग किलोमीटर अपतटीय क्षेत्र तेल और गैस खोज के लिए खोल दिया गया है। ओपन एकरेज लाइसेंसिंग प्रोग्राम (OALP) के तहत घरेलू और विदेशी कंपनियों की भागीदारी बढ़ी है और OALP राउंड–10 निवेश के लिए नए मानदंड तय कर सकता है।

उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की ये पहलें न केवल स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा दे रही हैं, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था के 6.5 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल करने में कोई बाधा नहीं

नई दिल्ली, 28 जुलाई।

भारतीय अर्थव्यवस्था तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है और चालू वित्त वर्ष (2025–26) में इसे 6.5 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर हासिल करने में किसी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ेगा। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के सदस्य नागेश कुमार ने रविवार को यह बात कही। कुमार ने 'पीटीआई वीडियो' के साथ साक्षात्कार में कहा कि दुनिया की सभी अर्थव्यवस्थाओं में भारत की स्थिति बेहतर बनी हुई है। उन्होंने कहा, ''वास्तव में, एक–तिहाई से ज्यादा वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं ऋण संकट से जूझ रही हैं... औद्योगिकीकृत अर्थव्यवस्थाएं भारी दबाव, ऊंची मुद्रास्फीति और आर्थिक वृद्धि में सुस्ती का सामना कर रही हैं।'' कुमार ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था निर्यात या व्यापार से अधिक घरेलू खपत और घरेलू निवेश पर टिकी है। इस वजह से आज भी भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, ''मुझे चालू वित्त वर्ष और अगले साल भारतीय अर्थव्यवस्था के 6.5 प्रतिशत से अधिक की दर से बढ़ने की राह में कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है।'' उन्होंने कहा, ''और, आप जानते हैं, उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में भी इस तरह की वृद्धि जारी रहेगी, और एक समय यह सात से 7.5 प्रतिशत पर पहुंच जाएगी।'' पिछले वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के 6.5 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमान के अनुसार, चालू वित्त वर्ष में भी देश की अर्थव्यवस्था इसी दर से बढ़ेगी। मुद्रास्फीति पर एक सवाल पर कुमार ने कहा कि वर्तमान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति लगभग दो प्रतिशत है और यह काफी हद तक एमपीसी (मौद्रिक नीति समिति) या आरबीआई द्वारा अपनाई गई नीति का परिणाम है।

हर घर जल: 12.44 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण घरों को नल के पानी का कनेक्शन दिया गया

नई दिल्ली, 28 जुलाई।

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री वी. सोमन्ना ने सोमवार को संसद को बताया कि जल जीवन मिशन (जेजेएम)–हर घर जल के तहत अब तक लगभग 12.44 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण घरों को नल के पानी के कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। मिशन की शुरुआत में, केवल 3.23 करोड़ (16.7 प्रतिशत) ग्रामीण घरों में ही नल के पानी के कनेक्शन होने की सूचना थी। वहीं, सरकार ने जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाने की घोषणा की है।

भारत सरकार ने अगस्त 2019 में केंद्र प्रायोजित योजना जल जीवन मिशन (जेजेएम) शुरू की थी, जिसका लक्ष्य 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) प्रदान करना है। जल शक्ति राज्य मंत्री वी. सोमन्ना ने एक लिखित उत्तर आज राज्यसभा में जानकारी दी है कि दीर्घकालिक स्थिरता और नागरिक–केंद्रित जल सेवा वितरण हेतु ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव और बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करते हुए मिशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण 2025–26 के दौरान कुल परिव्यय में वृद्धि के साथ जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाने की घोषणा की है।

तदनुसार, कुल परिव्यय में वृद्धि के साथ, अन्य बातों के साथ–साथ आगे के वित्तपोषण के लिए दिशानिर्देशों सहित, जल जीवन मिशन को 2028 तक जारी रखने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

ज्ञात हो, मिशन की शुरुआत में, केवल 3.23 करोड़ (16.7 प्रतिशत) ग्रामीण घरों में ही नल के पानी के कनेक्शन होने की सूचना थी। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 23 सितंबर 2025 तक दी गई जानकारी के अनुसार, जल जीवन मिशन (जेजेएम) : हर घर जल के तहत अब तक लगभग 12.44 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण घरों को नल के पानी के कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं।

इस प्रकार, 23 सितंबर 2025 तक देश के 19.36 करोड़ ग्रामीण घरों में से 15.67 करोड़ (80.95 प्रतिशत) से अधिक घरों में नल के पानी की आपूर्ति होने की सूचना है।

हेपेटाइटिस के खिलाफ मजबूती से आगे बढ़ रहा भारत– केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री

नई दिल्ली, 28 जुलाई।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सोमवार को विश्व हेपेटाइटिस दिवस के मौके पर कहा कि भारत इस खतरनाक बीमारी के खिलाफ मजबूती से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम के जरिए देशभर में लोगों की जान बचाने और बीमारी को खत्म करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह दिन लोगों में हेपेटाइटिस की जानकारी और उसकी रोकथाम के उपायों को लेकर जागरूकता फैलाने का बड़ा अवसर है।

गौरतलब है कि हर साल 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य वायरल हेपेटाइटिस के बारे में जानकारी बढ़ाना और इससे निपटने के लिए रोकथाम, जांच और इलाज के प्रयासों को मजबूत करना होता है। जेपी नड्डा ने इस साल की थीम 'हेपेटाइटिस : लेट्स ब्रेक इट डाउन' पर कहा कि यह थीम उन सामाजिक रुकावटों को खत्म करने पर जोर देती है, जो इस बीमारी के उन्मूलन में बाधा बनती हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक भारत हेपेटाइटिस बी और सी मामलों में चीन के बाद दुनिया में दूसरे स्थान पर है। साल 2022 के आंकड़ों के मुताबिक भारत में 2.98 करोड़ लोग हेपेटाइटिस बी और 55 लाख लोग हेपेटाइटिस सी से पीड़ित थे। यह संख्या वैश्विक हेपेटाइटिस मामलों का लगभग 11.6: है। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने कहा कि देश में हेपेटाइटिस के खिलाफ लड़ाई के लिए जागरूकता और समय पर जांच व इलाज को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि हमें नए तरीकों से लोगों को इसके रोकथाम के उपायों की जानकारी देनी होगी। भारत का राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम जांच, इलाज और बचाव की सुविधा मुहैया कराकर इस लड़ाई को मजबूती दे रहा है।

हेपेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है, जिसमें लिवर (यकृत) में सूजन आ जाती है और यह गंभीर लिवर रोग या कैंसर का रूप ले सकती है। यह बीमारी पांच प्रकार के वायरस –ए, बी, सी, डी और ई से होती है, जिनके फैलने के तरीके, गंभीरता और इलाज अलग–अलग होते हैं। विश्व हेपेटाइटिस दिवस समाज में फैले कलंक, जानकारी की कमी और इलाज तक सीमित पहुंच जैसी समस्याओं को दूर करने की जरूरत को उजागर करता है।

सुरक्षा और पर्यटन का अनूठा संगम.. द्रास में पर्यटकों के लिए खोला गया इंडस व्यू पॉइंट, आर्मी चीफ ने किया उद्घाटन

द्रास (करगिल), 28 जुलाई।

अब टूरिस्ट उस जगह को देख सकेंगे जहां से इंडस (सिंधु) नदी पाकिस्तान–अधिकृत बल्टिस्तान की ओर बहती है। करगिल विजय दिवस पर आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इंडस व्यू पॉइंट का उद्घाटन किया। भारतीय सेना ने बताया कि यह जगह न सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है बल्कि हमारे सैनिकों और पूर्व सैनिकों की बहादुरी का जीवंत अनुभव भी कराती है। यह इंडस व्यूपॉइंट बटालिक से करीब 10 किलोमीटर और लाइन ऑफ कंट्रोल (LOC) से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है।

यह व्यू पॉइंट उस क्षेत्र में है जहां से सिंधु नदी पाकिस्तान–अधिकृत बल्टिस्तान की ओर बहती है। यह सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं है बल्कि यहां कुछ अहम बेटल फील्ड भी हैं। जो हमारे वीर सैनिकों की शौर्यगाथा और दुश्मन की चौकियों की कहानी बताते हैं। इस व्यू पॉइंट का मकसद देशवासियों को यह महसूस कराना है कि हमारे सैनिकों ने यहां सेवा करते हुए हमेशा देश की रक्षा की है।

सेना ने कहा का यह व्यूपॉइंट सुरक्षा और पर्यटन के बीच संतुलन बनाने की कोशिश है ताकि लोग न सिर्फ प्रकृति का आनंद लें बल्कि देशभक्ति की भावना भी महसूस कर सकें। 'भारत रणभूमि दर्शन' प्रोग्राम के तहत कई बेटल

फील्ड को पर्यटकों के लिए खोला जा रहा है। ईस्टर्न लद्दाख में गलवान भी पर्यटकों के लिए खुलना है। गलवान वॉर मेमोरियल तैयार है और कभी भी इसे पर्यटकों के लिए खोला जा सकता है। उस जगह से वह ऊंचाई साफ देखी जा सकेगी जहां गलवान में भारत चीन को सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी।

'भारत रणभूमि दर्शन' प्रोग्राम में 'शौर्य गंतव्य' सियाचिन बेस कैंप, लिपुलेख दर्रा, बूमला, किबितु के साथ ही डोकलाम को भी शामिल किया गया है। यानी यहां टूरिस्ट को आने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उन जगहों पर टूरिजम को बढ़ावा दिया जा रहा है जहां पर लड़ाइयां लड़ी गई, जहां हमारे जाबांजों ने वीरता दिखाई और बलिदान दिया।

कंबोडिया और थाईलैंड 'तत्काल और बिना शर्त युद्धविराम' पर सहमत

कुआलालंपुर, 28 जुलाई।

मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने सोमवार को कहा कि कंबोडिया और थाईलैंड स्थानीय समयानुसार मध्यरात्रि (सोमवार दोपहर 12 बजे पूर्वी समय) से 'तत्काल और बिना शर्त युद्धविराम' पर सहमत हो गए हैं। यह घोषणा दोनों देशों की लंबी विवादित सीमा पर कई दिनों से चल रही झड़पों के बाद कही गयी।

मलेशिया के समाचार पत्र द स्टार ने प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के हवाले से कंबोडिया और थाईलैंड के बीच युद्धविराम वार्ता में बनी सहमति की घोषणा की। मलेशिया के अनुसार, दोनों देश 29 जुलाई को कंबोडियाई और थाई पक्षों के क्षेत्रीय कमांडरों की एक बैठक करेंगे।

युद्धविराम वार्ता के लिए मलेशिया पहुंचे कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन मानेट और थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री फुमथम वेचायाचाई ने राजधानी कुआलालंपुर के दक्षिण में पुत्रजया स्थित प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के आधिकारिक आवास पर मुलाकात की।

दोनों पक्षों ने एक–दूसरे पर सीमा पर हालिया झड़प शुरू करने का आरोप लगाया। थाई और कंबोडियाई अधिकारियों के अनुसार, इस लड़ाई में कम से कम 35 लोग मारे गए हैं और 200 से अधिक घायल हुए हैं। दोनों पक्षों के बीच सीमा विवाद दशकों पुराना है। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन ने युद्धविराम वार्ता में पर्यवेक्षकों की सहायता की भी पेशकश की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने थाईलैंड और कंबोडिया के नेताओं को चेतावनी दी थी कि अगर यह सीमा संघर्ष जारी रहा तो वह दोनों देशों के साथ व्यापार समझौता नहीं करेंगे।

इतिहास के पन्नों में 29 जुलाई: बाघ संरक्षण पर भारत की प्रतिबद्धता

नई दिल्ली, 28 जुलाई।

29 जुलाई का दिन इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए जाना जाता है। इस दिन भारत में बाघ संरक्षण पर जोर दिया गया था, जब 1973 में 'प्रोजेक्ट टाइगर' शुरू किया गया था। परियोजना के 50 साल पूरे होने पर आयोजित एक कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस (आईबीसीए) की शुरुआत भी की। इसका उद्देश्य बाघ और शेर समेत दुनिया की बिग कैट परिवार की सात प्रमुख प्रजातियों की रक्षा एवं संरक्षण करना है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कहते हैं कि वन्यजीव की सुरक्षा सार्वभौम मुद्दा है।

अन्य प्रमुख घटनाएं:– 1858– अमेरिका और जापान ने हैरिस संधि पर हस्ताक्षर किए, जिससे जापान में अमेरिकी वाणिज्यिक व राजनयिक विशेषाधिकार सुरक्षित हुए।

1876– भारत में 'इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस' की स्थापना हुई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में महत्वपूर्ण संस्थान है।

1899– पहला हेग कन्वेंशन, पहले औपचारिक बयानों के बीच अंतरराष्ट्रीय कानून में युद्ध और युद्ध अपराधों के कानूनों पर हस्ताक्षर किए गए थे।

1921 – जर्मनी में एडोल्फ हिटलर को नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी का नेता चुना गया।

1949 – ब्रिटिश ब्राडकॉस्टिंग कारपोरेशन का रेडियो पर प्रसारण शुरू।

1957 – संयुक्त राष्ट्र ने अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) का गठन किया।

1973 – भारत में 'प्रोजेक्ट टाइगर' की शुरुआत हुई, जिसका उद्देश्य देश के राष्ट्रीय उद्यानों में बाघों का संरक्षण करना था।

1980 – मॉस्को ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था।

1981 – ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स और राजकुमारी डायना की शादी हुई थी।

1983 – पहले चालक रहित विमान 'मिनी' ने सफलतापूर्वक उड़ान भरी।

1996 – चीन ने लोपनोर में अपना 45वां भूमिगत परमाणु परीक्षण किया।

2007– वैज्ञानिकों ने एथेंस में प्री हिस्टोरिका पीरियड के हाथी के दांत की खोज की।

2008– इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री एहुद ओल्मर्ट ने सीरिया के साथ चौथे दौर की शांति वार्ता के लिए अपने दो प्रतिनिधि तुर्किये भेजे।

2018 – इंडोनेशिया के लोमबोक द्वीप में 6.4 तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई।

भारतीय हथियारों की मांग तेजः ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया ने मानी भारत की ताकत

नई दिल्ली, 28 जुलाई।

ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारत के स्वदेशी हथियारों की अंतरराष्ट्रीय मांग तेजी से बढ़ी है। आर्मेनिया ने भारतीय हथियारों की तकनीकी क्षमताओं को समझने और नए रक्षा सौदे के लिए टॉप सैन्य अधिकारियों को दिल्ली भेजा है। भारत अब वैश्विक रक्षा बाजार में एक उभरती ताकत बनकर सामने आ रहा है।

22 अप्रैल, 2025 को जम्मू–कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसमें न केवल आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त किया गया, बल्कि पाकिस्तानी सेना को भी माकूल जवाब दिया गया। इस ऑपरेशन के दौरान भारत ने अपनी स्वदेशी रक्षा प्रणाली और हथियारों का प्रभावशाली प्रदर्शन किया, जिससे दुनियाभर में उसकी सैन्य तकनीक की सराहना होने लगी।

ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जिन हथियारों का उपयोग किया, उन्होंने साबित किया कि भारत का रक्षा सिस्टम अब चीन और तुर्किए के हथियारों से कहीं अधिक सक्षम है। इस कार्रवाई के बाद भारत की मिसाइल तकनीक, मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम की वैश्विक मांग में जबरदस्त उछाल आया है।

भारत की सैन्य क्षमता से प्रभावित होकर आर्मेनिया ने अपने टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली भेजा है, जिसका नेतृत्व कर्नल म्हेर इस्रायेल्यान कर रहे हैं। इस प्रतिनिधिमंडल का मकसद भारत में विकसित आधुनिक AK–203 असॉल्ट राइफल, फ्रंटलाइन सेंसर, स्मार्ट निगरानी प्रणाली और अन्य रक्षा उत्पादों की टेक्नोलॉजी को समझना और नई डील को अंतिम रूप देना है।

अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच लंबे समय से तनावपूर्ण संबंध हैं। अजरबैजान को तुर्किए का सैन्य समर्थन प्राप्त है और वह तुर्की के हथियारों से लैस है। इस खतरे के जवाब में आर्मेनिया भारत को स्ट्रैटेजिक रक्षा साझेदार के रूप में देखता है और भारत से अत्याधुनिक रक्षा प्रणाली खरीद रहा है।

2020 से अब तक आर्मेनिया ने भारत से 2 अरब डॉलर से अधिक के रक्षा सौदे किए हैं। इन सौदों में प्रमुख रूप से पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर तेज और सटीक मारक क्षमता, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम– कम ऊंचाई पर उड़ते ड्रोन और मिसाइल को नष्ट करने में सक्षम शामिल है। 2022 में हुए 720 मिलियन डॉलर के डील के तहत, आर्मेनिया भारत से 15 यूनिट आकाश–1S एयर डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है।

डिलीवरी और अगली खेप की तैयारी

इस डील की पहली बैटरी नवंबर 2024 में डिलीवर हो चुकी है

दूसरी बैटरी जुलाई 2025 के अंत तक दी जाएगी

आकाश–1S सिस्टम को आर्मेनिया ने खरीदकर भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय ग्राहक बनने का गौरव हासिल किया

नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 2025 का ड्राफ्ट जारी, भारत को 2030 तक डिजिटल लीडर बनाने की तैयारी

नई दिल्ली, 28 जुलाई।

भारत सरकार ने नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 2025 का ड्राफ्ट जारी कर दिया है, जिसका लक्ष्य देश को 2030 तक वैश्विक टेलीकॉम टेक्नोलॉजी का अगुवा बनाना है। इस नीति के तहत सरकार ने 6जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी अगली पीढ़ी की तकनीकों को बढ़ावा देने की रणनीति बनाई है। ड्राफ्ट में 10 लाख नई नौकरियों के सृजन और 10 करोड़ घरों तक हाई–स्पीड ब्रॉडबैंड पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा, नीति में डिजिटल समावेशन, साइबर सुरक्षा, और उद्योगों में तकनीकी नवाचार को प्रोत्साहित करने पर भी खास जोर दिया गया है।

यह नीति न सिर्फ डिजिटल बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने का वादा करती है, बल्कि ग्रामीण और दूरदराज़ के इलाकों तक तेज़ और सुलभ इंटरनेट सुविधा सुनिश्चित करने की दिशा में भी एक बड़ा कदम मानी जा रही है।

सरकार द्वारा जारी नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 2025 के ड्राफ्ट में बताया गया है कि यह नीति भारत के डिजिटल भविष्य की दिशा तय करेगी। प्रस्तावना में ज़िक्र है कि यह पॉलिसी देश को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व दिलाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है।

इस मसौदे में बताया गया है कि भारत को आने वाले वर्षों में जिन टेक्नोलॉजिकल बदलावों और चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, उन्हें ध्यान में रखते हुए यह नीति बनाई गई है। इसमें खासतौर पर 5ळ और 6ळ नेटवर्क, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और क्वांटम

कम्युनिकेशन जैसी उभरती तकनीकों को लेकर योजनाएं बनाई गई हैं। ड्राफ्ट में स्पष्ट किया गया है कि भारत को एक नॉलेज–बेस्ड और कनेक्टेड इकोनॉमी के रूप में स्थापित करने के लिए यह नीति डिजिटल बुनियादी ढांचे को मज़बूत करेगी, नवाचार को बढ़ावा देगी और तकनीकी आत्मनिर्भरता को बढ़ाएगी।

नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 2025 के ड्राफ्ट में सरकार ने ऐलान किया है कि देश में 10 लाख सार्वजनिक वाई–फाई हॉटस्पॉट लगाए जाएंगे। इसका उद्देश्य हर नागरिक को तेज़ और किफायती इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराना है, खासकर ग्रामीण और दूरदराज़ इलाकों में। प्रस्तावना में यह भी कहा गया है कि जैसे–जैसे दुनिया भर में नई तकनीकें ग्लोबल वैल्यू चेन को प्रभावित कर रही हैं, यह नीति भारत को उस बदलाव का एक सशक्त भागीदार बनाने की दिशा में काम करेगी। इसके ज़रिए भारत की डिजिटल क्षमता को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जाएगा।

शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल 'प्रलय' का सफल परीक्षण, 475 किमी. दूर था निशाना

नई दिल्ली, 28 जुलाई।

भारत ने सोमवार को सुबह 9.35 बजे ओडिशा के डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल श्प्रलयश का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल की परीक्षण रेंज 475 किलोमीटर तक थी। यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 500 किमी. तक है। इस मिसाइल को पश्चिमी और उत्तरी सीमा पर तैनात किये जाने की मंजूरी सरकार से मिल चुकी है। मिसाइल की जद में पाकिस्तान के कई प्रमुख एयरबेस और महत्वपूर्ण चीनी ठिकाने आएंगे।

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) ने नई पीढ़ी की सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की मिसाइल 'प्रलय' का उड़ान परीक्षण ओडिशा तट के कलाम द्वीप से किया। बैलिस्टिक मिसाइल ने 475 किलोमीटर तक की रेंज में अपने सभी उद्देश्यों को पूरा किया। इस दौरान कई उपकरणों के जरिए तट रेखा से इसके प्रक्षेपण की निगरानी की गई। मिसाइल ने उच्च डिग्री की सटीकता के साथ निर्दिष्ट लक्ष्य को निशाना बनाया। मिसाइल की सभी उप–प्रणालियों ने भी संतोषजनक प्रदर्शन किया। सभी सेंसर ने मिसाइल प्रक्षेपवक्र को ट्रैक करके सभी घटनाओं को कैप्चर किया। मिसाइल को उच्च–स्तरीय दुश्मन ठिकानों, जैसे हवाई अड्डे, आपूर्ति डिपो और सैन्य ठिकानों पर सटीक हमले के लिए डिजाइन किया गया है।

रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना की मारक क्षमता को बड़ा बढ़ावा देते हुए वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) और नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर तैनाती के लिए 'प्रलय' बैलिस्टिक मिसाइलों की एक रेजिमेंट की खरीद को मंजूरी दे दी है। चीन और पाकिस्तान के साथ सीमाओं पर तैनाती करने के लिए यह भारतीय सेना के लिए एक बड़ा निर्णय है, क्योंकि प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल 150–500 किलोमीटर के बीच लक्ष्य को मार सकती है। मिसाइल में एक निश्चित दूरी तय करने के बाद अपना रास्ता बदलने की क्षमता है। सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल 500–1000 किलोग्राम का भार वहन करने में सक्षम है। इसे मोबाइल लॉन्चर से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसकी तैनाती का उद्देश्य पश्चिमी (पाकिस्तान) और उत्तरी (चीन) दोनों सीमाओं पर विश्वसनीय प्रतिरोध और त्वरित पारंपरिक प्रतिक्रिया प्रदान करना है।

इस मिसाइल की जद में पाकिस्तान के मुशफ, नूर खान, रफीकी और मसरूर एयरबेस के साथ–साथ शिनजियांग में महत्वपूर्ण चीनी ठिकाने आएंगे। मिसाइल को पहले भारतीय वायु सेना में शामिल किया जाएगा, जिसके बाद

भारतीय सेना में शामिल किए जाने की संभावना है। इस मिसाइल प्रणाली का इस्तेमाल लंबी दूरी की दुश्मन वायु रक्षा प्रणालियों और अन्य उच्च–मूल्य वाले मिसाइलों को नष्ट करने के लिए किया जा सकता है। इन मिसाइलों को सशस्त्र बलों में शामिल करने के प्रस्ताव को ऐसे समय में मंजूरी दी गई है, जब भारत अपनी रॉकेट फोर्स बनाने की दिशा में काम कर रहा है, जो लंबी दूरी से दुश्मन के ठिकानों को मार गिरा सके। चीनी सेना के पास पहले से ही रॉकेट फोर्स है। भारत इस बैलिस्टिक मिसाइल 'प्रलय' को भी अपनी रॉकेट फोर्स में भी शामिल करने पर विचार कर रहा है।

अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन आज

नई दिल्ली, 28 जुलाई।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मंगलवार को यहां भारत मंडपम में अखिल भारतीय शिक्षा समागम–2025 का उद्घाटन करेंगे। शिक्षा मंत्रालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की पांचवीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य इस एक दिवसीय विचार–विमर्श कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है।

शिक्षा मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान में कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य एनईपी 2020 की उपलब्धियों की समीक्षा करना और भविष्य की रूपरेखा तैयार करना है। इस समागम में शिक्षाविदों, नीति निर्माताओं, उद्योग प्रतिनिधियों, अनुसंधान संस्थानों और सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की भागीदारी रहेगी। दिनभर चलने वाली विचार–विमर्श की शृंखला में शिक्षा को अधिक समावेशी, रोजगारोन्मुख, तकनीकी और नवाचार–आधारित बनाने पर चर्चा होगी। एनईपी 2020 के तहत बीते पांच वर्षों में उच्च शिक्षा और स्कूल शिक्षा में कई क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं। अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी), राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ), स्वयं, समर्थ, ओनोस, और मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसी योजनाओं ने उच्च शिक्षा में लचीलापन, पहुंच और गुणवत्ता को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है।

निसार की उल्टी गिनती शुरू, 30 जुलाई को होगा लॉन्च

नई दिल्ली, 28 जुलाई।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मिलकर एक अत्याधुनिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह विकसित किया है, जिसे 30 जुलाई 2025 को लॉन्च किया जाएगा। इस उपग्रह को भारत में निर्मित जीएसएलवी–एफ16 रॉकेट के जरिए 740 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाएगा। यह उपग्रह खराब मौसम, बादलों और बारिश के बावजूद दिन–रात पृथ्वी की स्पष्ट तस्वीरें लेने में सक्षम होगा। इसका उपयोग भूस्खलन, प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन की निगरानी के लिए किया जाएगा।

इसरो अध्यक्ष डॉ. वी. नारायणन ने चेन्नई हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत में बताया कि यह उपग्रह केवल भारत और अमेरिका ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए उपयोगी होगा। उन्होंने बताया कि इसरो फिलहाल 55 उपग्रहों का संचालन कर रहा है और आने वाले चार वर्षों में इन्हें तीन अलग–अलग श्रेणियों में विभाजित करने की योजना है। नारायणन ने सूर्य के अध्ययन के लिए भेजे गए आदित्य एल1 मिशन की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह उपग्रह 26 जनवरी को 1.5 किलोग्राम वजन के साथ लॉन्च किया गया था और इसने सूर्य से जुड़े अहम डेटा इसरो को भेजे हैं, जिनका वैज्ञानिक विश्लेषण जारी है।

मानव मिशन की तैयारियों पर बात करते हुए नारायणन ने बताया कि इस साल दिसंबर में एक मानवरहित मिशन लॉन्च किया जाएगा। अगर यह सफल होता है, तो अगले साल दो और मानवरहित मिशन भेजे जाएंगे। प्रधानमंत्री

की ओर से घोषित योजना के अनुसार, मार्च 2027 में भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया जाएगा, जिसके लिए श्रीहरिकोटा में पहला प्रक्षेपण वाहन तैयार किया जा रहा है।

इसरो प्रमुख ने चंद्रयान–4 मिशन के प्रति भी उत्साह जताया। यह मिशन चंद्रमा की सतह से नमूने लाने के लिए होगा और इसरो इसे पूरी तरह सफल बनाने को प्रतिबद्ध है। इसके बाद चंद्रयान–5 मिशन भारत और जापान का संयुक्त प्रोजेक्ट होगा, जो चंद्रमा की सतह पर 100 दिनों तक काम करेगा।

अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवसः बाघों के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना है इस दिन को मनाने का मकसद

नई दिल्ली, 28 जुलाई।

हर साल 29 जुलाई को दुनियाभर में अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। बाघों की घटती संख्या के कारणों को जानने के साथ ही उनके संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के मकसद से मनाया जाता है यह दिन। बाघ हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को स्वस्थ रखने और उसकी विविधता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर बाघ नहीं बचेंगे, तो इससे पूरा पारिस्थितिक तंत्र बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है। इसलिए इसका महत्व समझना जरूरी है।

अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने की शुरुआत साल 2010 में हुई थी। रूस के पीटर्सबर्ग में एक इंटरनेशनल कांफ्रेंस के दौरान 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाने का फैसला लिया गया था। इस क्रांफेंस में दुनियाभर के लगभग 13 देशों ने हिस्सा लिया था। बाघ दिवस मनाने का फैसला लेते हुए इन सभी देशों ने बाघों की संख्या को दोगुना करने का लक्ष्य रखा था।

इतने बड़े स्तर पर बाघ दिवस मनाने का उद्देश्य लोगों को बाघों के संरक्षण के प्रति तो जागरूक करना ही है, साथ ही उनके आवास की रक्षा और उन्हें कैसे बढ़ाया जाए, इस पर भी प्रकाश डालना है। पर्यावरण को होने

वाले नुकसान, जलवायु परिवर्तन के अलावा अवैध शिकार जैसे कई कारण हैं, जिनकी वजह से आज बाघों की संख्या लगातार कम हो रही है।

भारत सरकार ने साल 1973 में बाघों को संरक्षण प्रदान करने के मकसद से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी। इस प्रोजेक्ट के तहत कई सारे टाइगर रिजर्व स्थापित किए गए। कई तरह की नीतियां बनाई गईं, जिससे बाघों का शिकार रोका जा सके, उनकी संख्या बढ़ाने पर काम किया जा सके। जिसकी बदौलत अभी भारत में कुल 54 टाइगर रिजर्व हैं और यहां बाघों की संख्या बढ़ ही रही है, कम नहीं हो रही।

सरकार का बड़ा फैसलाः यूपीआई लेनदेन पर नहीं लगेगा जीएसटी! आम जनता को मिली राहत

नई दिल्ली, 28 जुलाई।

सरकार ने डिजिटल लेन–देन को लेकर देश के करोड़ों लोगों को राहत दी है। वित्त मंत्रालय ने राज्यसभा में स्पष्ट किया है कि 2000 रुपये से अधिक के यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) ट्रांजैक्शंस पर जीएसटी लगाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। यह जानकारी वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 22 जुलाई को राज्यसभा के मॉनसून सत्र के दौरान दी।

मंत्री ने बताया कि जीएसटी काउंसिल, जो केंद्र व राज्यों के प्रतिनिधियों वाली एक संवैधानिक संस्था है, उसने यूपीआई लेनदेन पर कोई कर लगाने की सिफारिश नहीं की है। उन्होंने कहा कि लोगों में हाल ही में जो भ्रम और आशंकाएं फैली थीं, उन्हें दूर करने के लिए यह स्पष्टीकरण दिया गया है।

यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस भारत में सबसे तेज, सुरक्षित और सुलभ डिजिटल भुगतान प्रणाली बन चुकी है। यह प्रणाली भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (छच्ब्) द्वारा विकसित की गई है और इसे भारतीय रिजर्व बैंक की मान्यता प्राप्त है। इसके माध्यम से उपभोक्ता किसी भी बैंक खाते से सीधे दूसरे बैंक खाते में रीयल–टाइम में ट्रांजैक्शन कर सकता है।

मोबाइल एप्स के माध्यम से संचालित होने वाला यह प्लेटफॉर्म, QR कोड, मोबाइल नंबर या UPI ID के जरिए भुगतान की सुविधा देता है, जिससे लेनदेन बेहद सरल हो जाता है।

हाल ही में कर्नाटक के लगभग 6,000 व्यापारियों को यूपीआई ट्रांजैक्शन डेटा के आधार पर जीएसटी डिमांड

नोटिस भेजे गए थे। इसके बाद यह आशंका फैलने लगी थी कि सरकार जल्द ही डिजिटल पेमेंट पर भी टैक्स लगाने वाली है। इन खबरों के चलते दिल्ली, मुंबई समेत कई शहरों के व्यापारियों ने यूपीआई से भुगतान लेने में हिचकिचाहट शुरू कर दी थी।

हालांकि अब सरकार के इस बयान के बाद स्थिति स्पष्ट हो गई है और व्यापारी व उपभोक्ता दोनों ही बिना किसी चिंता के यूपीआई का उपयोग कर सकेंगे। सरकार का यह निर्णय डिजिटल इंडिया मिशन को मजबूती प्रदान करेगा। यह न सिर्फ आम उपभोक्ताओं को राहत देगा, बल्कि छोटे और मध्यम व्यापारियों को भी प्रोत्साहित करेगा जो अपने रोजमर्रा के व्यापारिक लेन–देन के लिए यूपीआई पर निर्भर हैं।

फिलहाल यूपीआई के जरिए लेन–देन करने वाले उपभोक्ताओं और व्यापारियों को किसी प्रकार का अतिरिक्त कर नहीं देना होगा। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इस प्रकार के ट्रांजैक्शन पर जीएसटी लगाने की कोई योजना नहीं है।

भारत की चौथी महिला ग्रैंडमास्टर बनीं दिव्या देशमुख

नई दिल्ली, 28 जुलाई।

भारत की दिव्या देशमुख ने हमवतन कोनेरू हम्पी को टाईब्रेक में हराकर सोमवार को जॉर्जिया के बटुमी में फिडे महिला शतरंज विश्व कप का खिताब जीत लिया। 19 वर्षीय दिव्या ने पहले गेम में संतुलित ड्रॉ खेलने के बाद, मौजूदा महिला विश्व रैपिड चैंपियन हम्पी के खिलाफ दूसरे रैपिड गेम में जीत हासिल की।

दूसरे गेम में काले मोहरों से खेलते हुए दिव्या ने अनुभवी हम्पी की अंतिम गेम की गलतियों का फायदा उठाकर बढ़त हासिल की और अपने युवा करियर की सबसे बड़ी जीत हासिल की। मैच के निर्णायक क्षण में जब मुकाबला भारी मोहरों के साथ ड्रॉ की ओर बढ़ रहा था, हम्पी ने मोहरों की बलि देकर मैच को आगे बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन दिव्या के दबाव में उनका यह दांव नाकाम रहा। दिव्या ने जल्द ही अपनी रानी और एक हाथी की अदला–बदली की, ताकि वह ऐसा एंडगेम बना सके जहाँ वह अपनी मोहरों और समय की बढ़त के दम पर बढ़त हासिल कर सकें और ऐसा ही हुआ।

निर्णायक क्षण तब आया, जब हम्पी ने 54वीं चाल में --RŪf4 खेला, जिससे दिव्या के लिए एक फाइल खुल गई और उनके प्यादे को प्रमोशन की ओर बढ़ने का रास्ता मिल गया। दिव्या ने 67वीं चाल f5 के साथ लगभग खेल पर अपनी पकड़ खो दी थी, जिससे हम्पी को मुकाबले में

वापसी का मौका मिल सकता था। लेकिन समय के दबाव में हम्पी ने 67वीं चाल पर प्यादा बढ़ाने का गलत फैसला किया, जिससे उनका खेल वहीं समाप्त हो गया। 38 वर्षीय हम्पी ने 75वीं चाल के बाद हार स्वीकार कर ली।

यह टूर्नामेंट में किसी ग्रैंडमास्टर के खिलाफ दिव्या की लगातार चौथी जीत थी। इससे पहले उन्होंने चीन की झू जिनर को प्री–क्वार्टरफाइनल में, भारत की डी. हरिका को क्वार्टरफाइनल में और चीन की तान झोंगयी को सेमीफाइनल में हराया था। इस जीत के साथ दिव्या ने +50,000 (41.6 लाख रुपये) की पुरस्कार राशि भी अपने नाम की, जबकि हम्पी को +35,000 (29.1 लाख रुपये) मिले।